(ख) इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं इन आदेशों के अनुसरण में नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) निम्नलिखित राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार में आरक्षण किया है या उनको नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय किया है:—

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. जम्मू और कश्मीर
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. त्रिपुरा
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल

Central Housing Loans to Jammu and Kashmir State

1060. SHRI ABDUL AHAD VAKIL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Jammu and Kashmir Government has approached Central Government with a proposal for long term loans for constructing Housing colonies in the State; and

(b) if so, what is the Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b). The State Government of Jammu and Kashmir propose to borrow Rs. 20 crores from Housing and Urban Development Corporation for rural and urban housing schemes during the next plan period (i. e. 1979-83). The HUDCO have requested the State Government to send sepecific schemes which will be examined on merit and considered by them (HUDCO) provided these are as per the guidelines laid down by HUDCO.

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रही रजिस्टर्ड संस्थाएं

1061. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं कि (2 अक्तूबर से आरम्भ हुए) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रही संस्थाएं उन्हें दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग न कर पायें ;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई सरकारी संस्था भी भाग ले रही है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसके द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित किए जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : (क) प्रत्येक स्वैच्छिक एजेंसी को प्रगति रिपोर्ट और जांच लेखे विवरण भेजना होता है । कुछ मामलों में मौके पर निरीक्षण भी किया जाता है । संस्वीकृति की एक प्रति उन राज्य सरकारों को पृष्ठांकित की जाती है जिन्हें इस बात का निरीक्षण करना होता है कि निधियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है । इसके अतिरिक्त सरदार पटेल आर्थिक तथा सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद जैसी संस्थानों द्वारा क्षेत्र कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाता है ।

(ख) और (ग) इस समय 134 नेहरू युवक केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं । राजकीय तथा गैर-राजकीय एजेन्सियों के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है । किन्तु लगभग 10 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को 1983-84 के अन्त तक शामिल करने के उद्देश्य से इसका विस्तार निम्नलिखित कुल वार्षिक चरणों में किया गया है :—

(करोड़ों में)

वर्ष	वार्षिक शामिल	कुल शामिल
1978–79 (तयारी का वर्ष)	.15	.15
1979–80	.45	.60
1980–81	.90	1.50
1981–82	1.80	3.30
1982–83	3.20	6.50
1983–84	3.50	10.0